प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

24.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी से ही स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राज्यपाल आज शिमला जिला के फागू में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों की 'दीदियों' से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन सफलतापूर्वक 10वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान के तहत स्वच्छता लक्ष्य, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर केन्द्र में रहेंगे। शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जन अभियान में लोगों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने में पंचायत प्रतिनिधि और महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ भी किया। इसके अलावा राज्यपाल ने देवदार का पौधा रोपित कर वन विभाग के पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ भी किया।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू ने कहा है कि पंप स्टोरेज परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमौर जिला की एक हजार 6 सौ 30 मेगावाट की रेणुका जी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिला के ब्यास बेसिन में 2 सौ 70 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए आदर्श राज्य है और प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए वरदान हैं।

संसद–सम्मेलन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने विधायिकाओं की दक्षता और कामकाज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में शुरू हुए दो दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। ओम बिडला ने विधायी निकायों से विभिन्न मंचों पर चर्चा करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब प्रौद्योगिकी और संचार के साधन, लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं ऐसे में जन प्रतिनिधियों को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सत्ता में आने के बाद से कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को परेशान करने का काम कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार माफिया के प्रभाव में उद्योगों पर सरकारी नीतियों का दबाव डाल रही है और उद्योगपतियों का डराया–धमकाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सरकार ने उद्योगों को इस स्थिति में ला दिया है कि वे शटडाउन करने अपना विरोध दर्ज करवाने की योजना बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में सहयोग और रोजगार देने वाले उद्योगों को परेशान करके सरकार राज्य की आर्थिकी को चोट पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में विभिन्न स्तरों पर उद्योगों को रियायत दी जाती है ताकि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल सके लेकिन प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते उद्यमी हिमाचल से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

महिला स''ाक्तिकरण

केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, किसानों, मध्यम वर्ग की महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजना; शुरू की हैं। सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के विकास के लिए एक मजबूत पहल की है।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800–11–7800 के जरिए दे सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एस.एम.एस में प्राप्त लिंक का पालन करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। लोग नरेंद्र मोदी ऐप या माईगव ओपन फोरम के जरिए भी अपने सुझाव ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। लोग इस महीने की 27 तारीख तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।